"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांकं 11]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च 2003-फाल्गुन 23, शक 1924

ξx

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग २.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2003

क्रमांक आर. 479/2003/1/2/साप्रवि/लीव/आईएएस.—श्री एल. एन. सूर्यवंशी, कलेक्टर, बस्तर को दिनांक 24-2-2003 से 4-3-2003 तक (9 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा दिनांक 23-2-2003 सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

- 2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. एन. सूर्यवंशी को आगामी आदेश तक कलेक्टर, बस्तर, जिला बस्तर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.
- अवकांश अविध में श्री सूर्यवंशी को अवकाश वंतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.
- 4. ्रप्रमाणित किया जाता है कि श्री सूर्यवंशी यदि अवकाश पर

नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

5. श्री सूर्यवंशी के अवकाश काल में श्री शान्तनु, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जगदलपुर अपने कार्य के साथ-साथ कलेक्टर बस्तर का कार्य भी संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2003

क्रमांक ई-7-3/साप्रवि/2003/1/2/लीव/आईएएस.—डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 17-3-2003 से 22-3-2003 तक (6 दिवस) तक का अर्जित अवकाश देश विदेश योजना के तहत प्राप्त टिकिट का उपयोग बैंकाक एवं सिंगापुर प्रवास हेतु स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 14, 15, 16 एवं 23 मार्च 2003 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमित दी जाती है.

- 2. डॉ. आलोक शुक्ला को अवकाश से वापिस आने पर पुन: सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.
- 3. अवकाश काल में डॉ. आलोक शुक्ला को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.
- प्रमाणित किया जाता है कि यदि वे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.
- 5. डॉ. आलोक शुक्ला के अवकाश की अवधि में उनका कार्य श्री बी. एल. अग्रवाल, विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग अपने कर्त्तव्यों के साथ-साथ संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2003

्र 530/1324/2002/1/2/साप्रवि.—श्री सोनमणि वोरा, सहायक कलेक्टर, दुर्ग को दिनांक 5-6-2002 से 19-6-2002 तक (15 दिन) का अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

- श्री सोनमणि बोरा यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.
- 3. श्री वोरा को अवकाश काल में वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.
- 4. अवकाश से लौटने पर श्री वोरा को आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2003

क्रमांक 1281/1856/2002/राजस्व/सात.—राज्य शासन नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री का नोमिनक्लेचर परिवर्तित किये जाने की सहमति इस शर्त के साथ प्रदान करता है कि विभागीय क्रिया कलापों कर्त्तव्यों एवं विभागीय अधिकारियों के वेतनमानों आदि जो कि वर्तमान स्थिति में प्राप्त हो रहे हैं पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है :—

1. विभाग का नाम "नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग" के स्थान पर "संचालनालय, मुद्रण तथा लेखन सामग्री" Directorate of Printing and Stationery, (Chhattisgarh) परिवर्तित किया जाता है.

उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप विभागीय अधिकारियों के पदनाम निम्नानुसार परिवर्तित माने जावेंगे :--

| क्रमांक | • | वर्तमान : | उर्चिलित नाम | परिवर्तित | पदनाम |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--|---|--|
| | • • | हिन्दी | ′ अंग्रेजी | हिन्दी | अंग्रेजी |
| 1. | नियंत्रक, सामग्री. | मुद्रण तथा लेखन | Controller, Printing and Stationery. | संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री. | Director, Printing and Stationery. |
| 2. | संयुक्त रि लेखन स | नेयंत्रक, मुद्रण तथा गमग्री. | Joint Controller, Printing and Stationery. | संयुक्त संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री. | Joint Director, Printing and Stationery. |
| 3. | उप ऩियं | त्रक | Deputy Controller | उप-संचालक | Deputy Director |
| 4. | सहायक | नियंत्रक | Assitt. Controller | सहायक संचालक | Assist. Director |

- 2. उक्त पदनाम परिवर्तन के उपरान्त विभागीय अधिकारियों को वेतनमान वही प्राप्त होंगे जो कि उन्हें नाम परिवर्तन के पूर्व प्राप्त हो रहें थे तथा विभागीय अधिकारियों की वित्तीय शक्तियां एवं प्रशासनिक शक्तियां भी पूर्ववत ही रहेगी जो उन्हें पदनाम परिवर्तन के पूर्व प्राप्त थी.
- 3. विभागीय राजपत्र भर्ती नियमों में जहां-जहां नियंत्रक/अधीक्षक/संयुक्त नियंत्रक, उप नियंत्रक/उप अधीक्षक, सहायक नियंत्रक/सहायक अधीक्षक आया है उन्हें उक्त परिवर्तन की सूचना के उपरांत संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक एवं सहायक संचालक स्थापित माना जावेगा. स्वीकृत के उपरान्त राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील माने जावेगे.

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 104/CR/13/135 दिनांक 25-2-2003 द्वारा महालेखाकार छ. ग. रायपुर की ओर पृष्ठांकित की गई है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दुर्गेश मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर दिनांक 10 मार्च 2003

क्रमांक/एफ-9/26/सात/राजस्व/2003.—राज्य शासन एतद्द्वारा जिला दन्तवाड़ा एवं कांकेर के नामों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

| क्रमांक (1) | जिलों का पूर्व नाम (2) | जिलों का संशोधित नवीन नाम (3) |
|----------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1, | दन्तेवाड़ा | दक्षिण बस्तर, दन्तेवाडा |
| 2. | कांकेर | उत्तर बस्तर, कांकेर |

अब उपरोक्त जिले कालम नंबर तीन में दर्शाये गये नामों से जाने जावेंगे

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. तिवारी, अवर सचिव.

श्रमं विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक 539/2866/2002/16.—राज्य शासन संविदा श्रम(वि. एवं सं.)अधिनियम,1970 की धारा-4 सहपठित ठेका श्रम (वि. एवं सं) मध्यप्रदेश नियम, 1973 की नियम-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा राज्य सलाहकार ठेका श्रम मण्डल का गठन निम्नानुसार करता है :—

| (1) मान. श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन | अध्यक्ष |
|--|------------|
| (2) श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर | सदस्य/सचिव |
| (3) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक नि. वि. | संदस्य |
| (4) श्री एम. डी. भट्ट मिश्रा, प्रबंधक (मानव संसाधन विकास) एन.टी.पी.सी. कोरबा. | सदस्य |

नियोजक प्रतिनिधि

नियुक्ति प्रतिनिधि

(9) श्री अजीतलाल, बस्तर रोड टिकरापारा सदस्य धमतरी (बिड़ी श्रिमिक प्रतिनिधि)

(10) श्री नाथूलाल पाण्डे, अध्यक्ष, हिन्द मजदूर सदस्य सभा, झगराखण्ड, कोलियारी, कोरिया.

(11)

शासकीय उपक्रम के नियुक्ति प्रतिनिधि

(12) श्री गजेन्द्रसिंह, महासचिव, स्टील वर्क्स सदस्य यूनियन भिलाई.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. एस. मूर्ति, सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2003

क्रमांक 2828/डी. 15/54/2002/14-3 --जिला जांजगीर-चांपा में स्थापित अकलतरा मण्डी के पामगढ़ तहसील के गांवों को अपवर्जित करते हुए उसकी वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन किये जाने हेतु इस विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक 321/डी. 15/54/02/14-3 दिनांक 17 मई 2002 जारी किया गया था.

उक्त अधिसूच ग पर प्राप्त आपित्तर्यों एवं सुझावों के विश्लेषण के पश्चात् शासन द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि सीमाओं में परिवर्तन किया जाना आवश्यःस*ा*टी है. अत: उक्त अधिसूचना क्रमांक 321/डी. 15/54/02/14-3 एतद्द्वारा रद्द किया जाता है.

Raipur, the 10th February 2003

No. 2828/D. 15/54/2002/14-3.—Notification of this department vide No. 321-D-15/54/02/14-3 Dt. 17th May 2002 was issued to alter the existing limits of the established mandi Akltara of district Janjgir Champa after excluding the villages of Pamgarh Tahsil.

After analysing the objections/suggestion received on said notification the Government has decided that alter of limits is not needed.

Thus the said notification No. 321-D-15/54/02/14-3 stands cancelled herewith.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2003

क्रमांक 2837/डी. 8/2/03/14-2.—कृषि विभाग एदत्ह्वारा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक ई-1-5/2003/1/2, रायपुर, दिनांक 6-2-2003 के अनुपालन में डॉ. अजयवारा प्रसाद आदिथाला, भा.प्र.से. (1986) संचालक, कृषि एवं पशुपालन को उन्हें वृर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से आगामी आदेश पर्यन्त छत्तीसगढ़ गन्ना (प्रदाय एवं क्रय विनियमन) अभिनियम, 1958 की धारा-9 के तहत गन्ना आयुक्त नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. एल. जैन, उप-सचिव.

वित्त. तथा योजना विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2003

क्रमांक एफ 8-1/2001/23/आसां.—इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-12-2002 को अधिक्रमित करते हुए छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा-4, रूपधारा 3 (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम-2 में चिनिर्दिष्ट मंत्रि-परिषद् के सदस्यों को सारणी के कॉलम-3 में विनिर्दिष्ट जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है, जो समिति के अध्यक्ष भी होंगे, अर्थात् :—

| क्रमांक (1) | मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के नाम/विभाग (2) | जिला योजना सिमिति (3) | |
|----------------|---|--------------------------|---|
| 1. | श्री नंद कुमार पटेल, मंत्री, गृह | रायपुर | • |
| 2. | श्री भूपेश बघेल, मंत्री, राजस्व तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को छोड़कर). | विलासपुर | |
| 3. | भी महन्द्र कर्मा, मंत्री, उद्योग एवं खनिज (खनिज को छोड़कर) | दंतेवाड़ा (दक्षिण वस्तर) | |

| (1) | (2) | .(3) |
|------------|---|----------------------|
| 4. | श्री माधव सिंह धुव, मंत्री, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास | कांकेर (उत्तर बस्तर) |
| 5.1 | श्री अमितेष शुक्ल, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास | महासमुंद |
| 6. | श्री सत्यनारायण शर्मा, मंत्री, शिक्षा | दुर्ग |
| 7. | श्री डी. पी. धृतलहरे, मंत्री, वन | कवर्धा |
| ,8. | श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, मंत्री, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण. | सरगुजा |
| 9 | श्री चनेशराम राठिया, मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | कोरिया |
| 10. | श्री रविन्द्र चौबे, मंत्री, निर्माण, पर्यावरण एवं नगरीय विकास, विधि एवं विधायी तथा संसदीय कार्य. | रायगढ़ |
| 11 | ्श्री राम पुकार सिंह, मंत्री, उद्योग एवं खनिज, पर्यटन, संस्कृति, जनसंपर्क (उद्योग, पर्यटन एवं संस्कृति को छोड़कर). | जशपुर |
| 12. | श्री गंगूराम बघेल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्व तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व को छोड़कर). | जगदलपुर (बस्तर) |
| 13. | त्री ताम्रध्वज साहू, राज्य मंत्री, ऊर्जा एवं जल संसाधन तथा शिक्षा (जल संसाधन को छोड़कर). | धमतरी |
| 14. | श्री मोहम्मद अकबर, राज्य मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण. | राजनांदगांव 1 |
| 15: | डॉ. शक्राजीत नायक, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ऊर्जा एवं जल संसाधन (ऊर्जा की छोड़कर). | जांजगीर-चांपा |
| 16. | श्री तुलेश्वर सिंह, राज्य मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास | कोरबा |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमृता बेग, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2003

• क्रमांक 1227/डी-366/21-ब/छ.ग./2003.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमित से राज्य सरकार, एतद्द्वारा एक प्राधिकरण का गठन करती है जो निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रूप में जाना जायेगा.

अनुसूची

| अनुक्रमांक | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | जिले के लिए |
|------------|---------------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | बस्तर (जगदलपुर) | 1. जगदलपुर |
| • | | 2. दंतेवाड़ा |
| | 4 | 3. कांकेर |
| 2. | ्र बिलासपुर | 1. बिलासपुर |
| | - | 2. जांजगीर-चांपा |
| • | • | 3. कोरबा |
| 3. | दुर्ग | 1. दुर्ग |
| 4. | रायगढ़ | 1. रायगढ़ |
| | | · 2. जशपुर |
| 5. | रायपुर | ़ 1. रायपुर |
| • | • : | 2. धमतरी |
| , | | 3. महासमुन्द |
| . 6. | राजनांदगांव | , १ राजनांदगांव |
| | | |
| 7. • | सरगुजा अविकापुर | - 1. सर्गुजा |
| | | 2. कोरिया |

Raipur, the 11th February 2003

No. 1227/D-366/21-B/CG/2003.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 9 of the Legal Service authority Act, 1987 (No. 39 of 1987) and with the concurrenct of the Hon'ble Chief Justice of Chhattisgarh, the State Government hereby constitute an authority known as District Legal, Service Authority as the following Schedule:—

SCHEDULE

| S. No. | District Legal Services Authority at (2) | For the District of (3) |
|--------|--|---|
| 1. | Bastar at Jagdalpur | Jagdalpur Dantewara Kanker. |
| 2. | Bilaspur | 1. Bilaspur 2. Janjgir-Champa 3. Korba |
| 3. | Durg | 1. Durg |
| 4. | Raigarh | Raigarh Jashpur |
| 5. | Raipur | Raipur Dhamtari Mahasamund. |
| 6. | Rajnandgaon | 1. Rajnandgaon |
| 7. | Surguja Ambikapur | Surguja Koria |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2003

क्रमांक एफ-1-7/18/2003.—राज्य शासन, एतद्द्वारा नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 7 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर वृहत्तर नगरीय क्षेत्रों की अधिसूचना हेतु एक लाख या इससे अधिक आबादी का मापदण्ड निर्धारित करता है.

Raipur, the 28th February 2003

No. F-1-7/UAD/18/2003.—In exercise of the powers conferred under Section 7 (2) of Chhattisgarh Municipal Corporation Act. 1956, the State Government hereby, assigns population as one lac or more for an area to be declared as Municipal Corporation.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2003

क्रमांक एफ-1-7/18/2003.—राज्य शासन, एतद्द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर लघुत्तर नगरीय क्षेत्रों की अधिसूचना हेतु बीस हजार से अधिक परन्तु एक लाख से कम आबादी का मापदण्ड निर्धारित करता है.

Raipur, the 28th February 2003

No. F-1-7/UAD/18/2003.—In exercise of the powers conferred under Section 5 (2) of Chhattisgarh Municipalities Act. 1961, the State Government hereby, assigns population as more than twenty thousand but less than one lac for an area to be declared as Municipal Council.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2003

क्रमांक एफ-1-7/18/2003.—राज्य शासन, एतद्द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर संक्रमणशील क्षेत्रों की अधिसूचना हेतु पांच हजार से अधिक परन्तु वीस हजार से कम आबादी का मापदण्ड निर्धारित करता है.

Raipur, the 28th February 2003

No. F-1-7/UAD/18/2003.—In exercise of the powers conferred under Section 5 (2) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961, the State Government hereby, assigns population as more than five thousand but less than twenty thousand for an area for to be declared as Nagar Panchayat.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. सिन्हा, विशेष सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक एफ-5-10/2001/खाद्य/29.—राज्य शासन, एतद्द्वारा बुक ऑफ फायनेशियल पावर्स 1995 भाग-1 सेक्शन 1 की कंडिका-1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर को विभागाध्यक्ष घोषित करता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2003

- क्रमांक 955/315/ज.सं.वि./2002.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित अधीक्षण यंत्रियों को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, कार्यग्रहण करने के दिनांक से, स्थानापत्र रूप से मुख्य अभियंता के पद पर वेतनमान रुपये 16,400-450-20,000 में पदोन्नति प्रदान की जाती है :—
 - 1. श्री आर. के. खरे,
 - 2. श्री डी. दास गुप्ता,
- उक्तं दर्शित अधिकारियों की विस्तृत पदस्थापना पृथक् से जारी की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. डी. दीवान, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बस्तर , दिनांक 31 जनवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2002-03.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्र. एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :---

अनुसूची

| | 3 | र्मि का वर्णन | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------|---------|---------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर . | जगदलपुर | जमावाङा | 0.131 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, जगदलपुर. | जमावाड़ा मुरमा मार्ग निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा लोक निर्माण विभाग (भ/स) जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर , दिनांक 31 जनवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/2/अ-82/2002-03. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्र. एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

| | 9 | मि का वर्णन | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|-------|---------|-------------|----------------------------------|---|-----------------------|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | जाटम | 1.187 | कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर. | डोंगामं जलाशय निर्माण |

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर , दिनांकं 31 जनवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/3/अ-82/2002-03. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्र. एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

| , | · મૃ | मि का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|-------|---------|-------------|----------------------------------|--|--|
| ज़िला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | करनपुर | 4.095 | कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर. | भालूगुड़ा उद्वहन सि ंच ाई योजना. |

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर , दिनांक 31 जनवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/4/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्र. एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

| | બૃ | ्मि का वर्णन | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------|---------|--------------|----------------------------------|---|---|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| . बस्तर | जगदलपुर | तुसेल | 3.220 | कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर. | तुसेल् जलाशय नहर एवं स्पिल चैनल निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

वस्तर , दिनांक 31 जनवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/5/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्र. एक की धारा 4 की उपधारों (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उक्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :---

अनुसूची

| | ¥ | ्मि का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|-------|---------|--------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| जিলা | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | · के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | ़ का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | घाटपदमुर | 1.814 | कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., , जल संसाधन विभाग, जगदलपुर. | कुम्हराबन्ड उद्वहन सिंचाई योजना. |

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा अदेशानुसार, एल. एन. सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/914.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | , | भूमि का वर्णन | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|----------------------|----------------------------------|---|-------------------|
| জিলা | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | · (4) | (5) | · (6) |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | बिर्रा प.इ.नं. 22 | 0.477 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 2, चांपा | बिर्रा डि. ब्यू. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/915.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

| | | भूमि.का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|----------------------|----------------------------------|--|---------------------|
| <u> </u> | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | . (5) | (6) |
| जांजगोर-नांपा | चांपा | विर्रा प.ह.नं. 22 | 1.671 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 2, चांपा. | बिर्रा सब डि. ब्यू. |

क्रमांक क/भू-अर्जन/916.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | ं के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजेपुर | चिस्दा प.ह.नं. 25 | 0.231 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 2, चांपा. | बिर्रा संब डि. ब्यू. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/917.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उद्घेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | भूमि का वर्णन | | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------------|--------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | कमरीद प.ह.नं. ४ | 1.133 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 2, चांपा. | फरसवानी उप शाखा |

क्रमांक क/भू-अर्जन/918.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची -

| • | 9 | पूमि का वर्णन | - | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|-------|--------------------|-----------------------------------|--|-------------------|--|
| সিলা | तहसील | नगर/ग्राम | लंगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | कमरीद प.ह.नं. 4 | 0.707 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 2, चांपा. | फरसवानी उप शाखा | |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/919.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दो गई शक्तियों को गयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | S | भूमि का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|--------------------|----------------------------------|--|---|
| जिला - | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | • का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | . (6) |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | कमरीद प.ह.नं. 4 | 0.101 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 2, चांपा. | कोसमंदा माइ. नं.3 के अंतर्गत सब माइनर. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्रमांक क/भू-अर्जन/920.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | . • | भूमि का वर्णन | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|--------------|-------|-----------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीरचांपा | चांपा | भंवरमाल प.ह.नं. 11 | 0.081 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 2, चांपा. | चांपा शाखा नहर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/921.—चृंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | | भूमि का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|-------|-----------------------|----------------------------------|--|-------------------|--|
| जिला . | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | . (6) | |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | भंवरमाल प.ह.नं. 11 | 0.237 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 2, चांपा. | रोहदा डि. ब्यू. | |

क्रमांक क/भू-अर्जन/922.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

| अनसची | |
|-------------|--|
| ~ (, 1, 1), | |

| | ٩ | भूमि का वर्णन | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|-------|---------------------|----------------------------------|---|----------------|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | सोंठी प.ह.नं. 10 | 0.129 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 2, चांपा | चांपा शाखा नहर |

भूमि का नक्शा ('प्लान) भू–अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/923.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उणबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|---------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | लखाली प.ह.नं. 14 | 0.424 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. २, चांपा. | लखाली डि. ब्यू. |

क्रमांक क/भू-अर्जन/924.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | | भूमि का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-----------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वास प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | . (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | अमलडीहा प.ह.नं. 21 | 0.360 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 2, चांपा. | फरसवानी उप शाखा |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/925.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उख्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | 9 | भूमि का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------|
| जिला | - तहसील | नग्र∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | जाटा प.ह.नं. 4 | 0.149 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 2, चांपा. | कोसमंदा माइनर नं. 3 |

क्रमांक क/भू-अर्जन/926.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | g | नूमि का वर्णन | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|-------|----------------------|----------------------------------|---|-------------|
| जिला | तहसील | ्नगर⁄ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | कुरदा . प.ह.नं. 1 | 0.226 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 2, चांपा | कुरदा माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/927.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | . 4 | भूमि का वर्णन | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|-------|------------------------|----------------------------------|--|-----------------|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6). |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | तालदेवरी प.ह.नं. 20 | 0.274 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 2, चांपा. | बिर्स डि. ब्यू. |

क्रमांक क/भू-अर्जन/928.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उछ्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि . संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | 9 | भूमि का वर्णन | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|----------------------|------------------------------------|--|-------------------|
| जিলা | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल ' (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | , चांपा | चोरिया प.ह.नं. 13 | 0.085 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 2, चांपा• | लखाली डि. ब्यू. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/929.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

| | 9 | भूमि का वर्णन | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजेपुर | घिवरा प.ह.नं. 24 | 0.625 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 2, चांपा. | बिर्रा सब डि. ब्यू. |

क्रमांक क/भू-अर्जन/930.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17-की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | | भूमि का वर्णन | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|------------------|---------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल ' (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) ⁻ | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजेपुर | घिवरा | 0.667 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो | हसौंद वितरक |
| | | प.ह.नं. 24 | • | नहर सं. क्र. 2, चांपाः | • |

भूमि का नंक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/931.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संवंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधार। द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | | भूमि का वर्णन | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-----------|--------------------|------------------------------------|--|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल , (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | . (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | - जैजेपुर | हसौद प.ह.नं. 38 | 0.267 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 2, चांपा. | हसौद वितरक |

क्रमांक क/भू-अर्जन/932.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

| | | भूमि का वर्णन | • | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|---|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जै जेपुर | पेंड्रीसुकुल प.ह.नं. 26 | 0.243 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 2, चांपा | हसौद वितरक |

. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांप(, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/933.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| · | • | भूमि का वर्णन | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | पलाड़ीखुर्द प .ह.नं. 15 | 0.538 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 6, सक्ती. | पलारी सब माइनर नं. 3 | |

क्रमांक क/भू-अर्जन/934.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | - 4 | भृमि का वर्णन | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| जिला | वहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | सकी | बेल्हाडीह प.ह.नं. 11 | 0.679 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो ः नहर सं. क्र. 6, सक्ती. | हरदी उप शाखा |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/935.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उष्टेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | 9 | मूमि का वर्णन | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|-------|----------------------------|----------------------------------|--|-------------------|--|
| জিলা - | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | धनपुर प.ह .नं. 1 | 0. 58 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो . नहर सं. क्र. 6, सक्ती. | धनपुर माइनर. | |

क्रमांक क/भू-अर्जन/936.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | | भूमि का वर्णन | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | . (5) | (6) |
| जांजगीर~चांपा | सक्ती | डूमरपारा प.ह.नं. 14 | 0.844 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 6, सक्ती. | डूमरपारा सब माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/937.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|-----------------------|---------|---------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|
| जिला | तहसील . | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) · | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चां पा | पामगढ़ | डोंगा कोहरौद प.ह.नं. 9 | 0.410 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. | डोंगा कोहरौद माइनर नं. 3 |

क्रमांक क/भू-अर्जन/938. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दो जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

| ٠ | 9 | मूमि का वर्णन | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|--------|-----------------------|----------------------------------|--|---------------------|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | पामगढ़ | पेंड्री प.ह.नं. 14 | 0.837 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. | पेंड्री माइनर नं. 3 |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/939.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | 1 | भूमि का वर्णन | धारा 4 की उपधारा (2) | . सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|--------|-----------------------|----------------------------------|--|------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | पामगढ़ | बारगांव प.ह.नं. 13 | 0.234 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर- | - नेवराबंद माइनर |

क्रमांक क/भू-अर्जन/940.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उन्नेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | 9 | नूमि का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|----------|---------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | . का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | पामगढ़ 、 | कोहका प.ह.नं. 16 | 0.308 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर- | कोहका वितरक |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू–अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/941.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उक्षेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | • | भूमि का वर्णन | | धारा 4 को उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|--------|----------------------|----------------------------------|---|-------------------|--|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| जांजगीर-चांपा | पामगढ़ | बिलारी प.ह.नं. 16 | 0.600 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर | कोहका उप शाखा | |

क्रमांक क/भू-अर्जन/942.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :--

अनुसूची

| 1 | 9 | नूमि का वर्णन | · | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|----------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | . के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जांजगीर | करमंदा प.ह.नं. 31 | 0.636 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव बरॉज जल प्रबंध संभाग, रामपुर/कोरबा. | करमंदा माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/943.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | | भूमि का वर्णन | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|--------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | ं का वर्णन |
| (1) | (2) | .(3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | .सक्ती | पलाड़ीकला प.ह.नं. 15 | 1.096 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो ्नहर सं. क्र. 6, सक्ती | पलाड़ी सब माइनर |

क्रमांक क/भू-अर्जन/944.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

| | | भूमि का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | डूमरपारा प.ह.नं. 14 | 0.008 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 6, सक्ती. | हरदी शाखा नहर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/945.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | 9 | भूमि का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|-------|---------------------|----------------------------------|--|-------------------|--|
| জিলা | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | े का वर्णन | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | लहंगा प.ह.नं. 14 | 0.040 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 6, सक्ती. | दुरपा माइनर | |

क्रमांक क/भू-अर्जन/946. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

| | . 9 | भूमि का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|----------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | ं के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | छिता पंडरिया प.ह.नं. 16 | 1.162 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 6, सक्ती | छिता पंडरिया माइनर नं. 2 |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/947.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | 9 | भूमि का वर्णन | - | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन 💙 |
|---------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | . का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | , जैजैपुर | दर्राभाठा प.ह.नं. 17 | 1.176 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 6, सक्ती. | छिता पंडरिया माइनर नं. 1 |

0

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/948.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उझेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | 9 | र्मि का वर्णन | • | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|----------------|---------|---------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| जिला | - तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| ज़ांजगीर-चांपा | सक्ती | लवसरा प.ह.नं. 11 | 0.540 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 6, सक्ती- | हरदी माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/949.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा ४ को उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | पा मगढ़ | रसोटा <i>"</i> प.ह.नं. 12 | 0.121 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रवंध संभाग, जांजगीर. | डोंगा कोहरौद उपशाखा अंतर्गत माइनर नं. 7. |

0

क्रमांक क/भू-अर्जन/950.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | | भूमि का वर्णन | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|----------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | पिपरदा प.ह.नं. 10 | 0.081 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग. क्र. 2, चांपा | पुछेली माइनर. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/951.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

| | ٩ | भूमि का वर्णन | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|-------|-------------------------|----------------------------------|---|-------------------|
| जিলা | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | संजयग्राम प.ह.नं. 13 | 0.851 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 6, सक्ती | मछुआ भांठा माइनर. |

क्रमांक क/भू-अर्जन/952.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | | भूमि का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|---------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजेपुर | छिता पंडरिया प.ह.नं. 1 | 1.240 · | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 6, सक्तीः | छिता पंडरिया माइनर नं. 1 |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/953.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उझेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपवन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची -

| • | | भूमि का वर्णन | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|---------|---------------------|----------------------------------|--|-------------------|--|
| जिला . | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| जांजगीर-चांपा | जैजेपुर | डोंगया प.ह.नं. 4 | 0.209 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 4, डभरा | कारीगांव माइनर. | |

क्रमांक क/भू-अर्जन/954.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

| | _^ |
|---------|-----|
| अनस | चा |
| _່.ວ່.ເ | ` ' |

| | • | भूमि का वर्णन | | धारा ४ की उपधारा (2) | . सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|---------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------|--|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | ् जैजैपुर प.ह.नं. 23 | 2.000 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती. | भाटापारा माइनर | |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/955.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

| | | भूमि का वर्णन | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|---|---------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) . |
| जांजगीर-चांपा | जै जैपुर | जैजैपुर प.ह.नं. 23 | 3.307 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो - नहर सं. क्र. 3, सक्ती. | मुक्ता सब डि. ब्यू. |

क्रमांक क/भू-अर्जन/956.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|------------------------|----------------------------------|---|-------------------|
| <u> </u> জিলা | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | चोरभठ्ठी प.ह.नं. 25 | 3.530 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती | मुक्ता वितरक |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/957.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------------|
| जिला | तहसील · | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | मुक्ता प.ह.नं. 24 | 4.684 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती, | मुक्ता सब डि. ब्यू. |

क्रमांक क/भू-अर्जन/958.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

| | ^ |
|------|----|
| अनसः | वा |

| | 9 | भूमि का वर्णन | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|---------|-----------------------|----------------------------------|--|----------------|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | जैजैपुर प.ह.नं. 23 | 1.183 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती. | मछुआडीह माइनर. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/959.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|------------------------|----------------------------------|---|--------------------|
| जिला | तहसील | नगर ∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | चोरभठ्ठी प.ह.नं. 25 | 0.740 | कार्यपालून यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती. | मछुआडीह माइनर - |

क्रमांक क/भू-अर्जन/960.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

| · | 9 | भूमि का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|-----------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) · | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | जैजैपुर प.ह.नं. 23 | 0.929 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती. | मछुआडीह सब माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/961.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | 9 | भूमि का वर्णन | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|---------|------------------------|----------------------------------|--|-------------------|--|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम . | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| जांजगीर–चांपा | जैजैपुर | चोरभठ्ठो प.ह.नं. 25 | 1.813 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती. | चोरभठ्ठी माइनर | |

क्रमांक क/भू-अर्जन/962.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|----------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | मुक्ता प.ह.नं. 24 | 0.299 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती. | चोरभठ्ठी माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/963.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू— अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू—अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची -

| | • | भूमि का वर्णन | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|---------|----------------------|----------------------------------|--|-----------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर मंं) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | अरसिया प.ह.नं. 32 | 3.717 | कार्यपालन यंत्रो, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती. | सेन्दरी उप शाखा |

क्रमांक क/भू-अर्जन/964.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपु र | सेंदरी प.ह.नं. 27 | 3.259 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती. | सेंदरी माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/965.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | • | भूमि का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|-----------------------|----------------------------------|--|--------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | परसाडीह प.ह.नं. 27 | 1.132 | कार्यपालम यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती. | परसाडीह सब माइन्र. |

क्रमांक क/भू-अर्जन/966.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | | भूमि का वर्णन | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|--|-------------------|--|
| जিলা | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी - | का वर्णन | |
| (1) | (2) | , (3) | (4) | (5) | (6) | |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर [,] | घोराडीपा प.ह.नं. 27 | 0.052 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती. | घोराडीपा माइनर | |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/967.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा ४ की उपधारा (2) | ् सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|-----------------------|----------------------------------|--|---------------------|
| <u> </u> | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | परसाडीह प.ह.नं. 23 | 2.659 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती. | परसाडीह माइनर |

क्रमांक क/भू-अर्जन/968.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उद्घेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | | भूमि का वर्णन | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|----------------------|----------------------------------|---|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) . | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | सेंदरी प.ह.नं. 24 | 0.804 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती | परसाडीह माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा _दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/969.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता गड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उक्षेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

| | | भूमि का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|-----------------------|----------------------------------|---|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम ` | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | परसाडीह प.ह.नं. 27 | 3.093 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती . | घोराडीपा माइनर |

क्रमांक क/भू-अर्जन/970.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

| 21211 | ना |
|-------|----|
| 23.14 | ч |
| - O 0 | |

| भूमि का वर्णन | | | | धारा:4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|---------|----------------------|----------------------------------|--|---------------------|--|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | सेंदरी प.ह.नं. 24 | 5.271 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. ३, सक्ती. | सेंदरी सब डि. ब्यू. | |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू–अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/971.—चूंिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

| • | 9 | भूमि का वर्णन | • | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|--------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|--|---------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा ' | जैजैपुर | जैजैपुर प.ह.नं. 23 | 4.522 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर्र सं. क्र. ३, सक्ती∗ | जैजैपुर माइनर नं. 3 |

क्रमांक क/भू-अर्जन/972.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | • | भूमि का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|-----------------------|----------------------------------|--|---------------------|
| जिला _ | ्रतहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | जैजैपुर प.ह.नं. 23 | 1.368 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्तीः | सेंदरी सब डि. ब्यू. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/973.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उक्षेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपवन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | | भूमि का वर्णन | | धारा ४ की उपधारा (2) | ं सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|-----------------------|----------------------------------|--|---------------------|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | अरसिया प.ह.नं. 227 | 2.631 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती. | अरसिया माइनर नं. 1 |

क्रमांक क/भू-अर्जन/974.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गयं सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

| | ^ |
|-------|-----|
| अनम | ਜ਼ਾ |
| 1.7.2 | ٦, |

| | • | भूमि का वर्णन | ं धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|---------|-----------------------|----------------------------------|--|--------------------|
| जিলা | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| · (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | अरसिया प.ह.नं. 227 | 1.885 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती. | अरसिया माइनर नं. 2 |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/975.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| • | | भूमि का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|----------------|-------|--------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | . के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| ंजांजगीर-चांपा | सक्ती | सक्ती प.ह.नं. 8 | 5.487 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती. | सक्ती उप शाखा |

क्रमांक क/भू-अर्जन/976.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उक्षेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | दर्राभांठा प.ह.नं. 1 | 0.308 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो न नहर सं. क्र. 3, सक्ती. | मलनी वितरक |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/977.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपयन्थों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की 'सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

| | | भूमि का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|-----------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | खम्हरिया प.ह.नं. 6 | 1.886 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती. | मलनी वितरक |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कांकेर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 5 फरवरी 2003

क्रमांक 257/भू-अर्जन/1/अ-82/2000-01. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उक्षेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| ्भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|----------------|---------|-------------|----------------------------------|---|---|
| ्र जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | . (6) |
| कांकेर | पखांजूर | सत्यानंदनगर | 2.73 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कांकेर. | लघु जलाशय सिंचाई हेतु केनाल निर्माण. |

कांकेर, दिनांक 5 फरवरी 2003

क्रमांक 260/भू-अर्जन/2/अ-82/2000-01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | 3 | मूमि का वर्णन | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|--------|---------|---------------|----------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कांकेर | पखांजृर | चांदीपुर | 2.33 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कांकेर. | लघु जलाशय सिंचाई हेतु केनाल निर्माण बाबात्. |

कांकेर, दिनांक 5 फरवरी 2003

क्रमांक 263/भू-अर्जन/3/अ-82/2000-01. —चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में विर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|------------|----------------------------------|---|---|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कांकेर ं | पखांजूर | . हरिहरपुर | 5.222 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कांकेर. | लघु जलाशय सिंचाई हेतु केनाल निर्माण. |

कांकेर, दिनांक 5 फरवरी 2003

क्रमांक 269/भू-अर्जन/5/अ-82/2000-01. —चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में विर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंग, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | 9 | र्गुमि का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|--------|---------|--------------------------|----------------------------------|---|---|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कांकेर | पखांजूर | हरिहरपुर योगेन्द्रनगर | 4.299 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कांकेर. | लघु जलाशय सिंचाई हेतु केनाल निर्माण. |

कांकेर, दिनांक 5 फरवरी 2003

क्रमांक 266/भू-अर्जन/5/अ-82/2000-01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|---------|-----------|------------------------------------|---|---------------------------------------|----|
| जিলা | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल . (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| कांकेर | पखांजूर | चांदीपुर | 4.27 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कांकेर. | लघु सिचाई जलाशय हेर् केनाल निर्माण | तु |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. धूब, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 30 जनवरी 2003

क्रमांक 669/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क) एवं सन् 1984 के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| .• | | भूमि का वर्णन | | ्रधारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|----------|------------|---------------------|------------------------------------|--|---------------------------|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | 'लगभग क्षेत्रफल '(हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | , का वर्णन |
| (1) | '· · (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| ं कोरिया | बैकुन्उपुर | बैकुन्छपुर-मोदीपारा | 3.430 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बैकुन्डपुर कोरिया (छ.ग.) | बड़गांव नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्या (प्लान) जिलाध्यक्ष जिला कोरिया (बैकुन्ठपुर) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 30 जनवरी 2003

क्रमांक 669/भू-अर्जन/2003.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1984 (क) एवं सन् 1984 के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उद्देखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| | | भूमि का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|--------|-----------------|--------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कोरिया | वैकुन्ठपुर ं | बैकुन्ठपुर-बड्गांव | 0.848 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बैकुन्ठपुर कोरिया (छ.ग.) | ं बड़गांव नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) जिलाध्यक्ष जिला कोरिया (बैकुन्ठपुर) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 30 मई 2002

रा. प्र. क्र. 22/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार संभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|--------|-----------|----------------------------------|---|--|
| जিলা | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | राजपुर | आरा | 0.121 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2 अंबिकापुर. | गागर व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 30 मई 2002

रा. प्र. क्र. 23/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार संभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| | | र्मि का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|--------|--------|---------------|----------------------------------|---|---|
| जिला | तहसील | नगर⁄ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा . प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | . (6) |
| सरगुजा | राजपुर | मुस्का | 3.880 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2 अंबिकापुर. | मुरका जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

रा. प्र. क्र. 5/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूसि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| • • | 9 | भूमि का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|----------|---------|---------------|----------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा . | सूरजपुर | गिरजापुर : | 1.20 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर | गिरजापुर जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्सा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुंजा, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

रा. प्र. क्र. 6/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| | भूमि का वर्णन | | • | धारा ४ की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|--------|---------------|-----------|----------------------------------|--|--------------------------|
| जिला | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | सूरजपुर | बसदेई | 0.14 | अनुविभागीय अधिकारी, लो. नि. | बसदेई-जूर मार्ग पर गोबरी |
| • | | | • | ृ वि. सेतु निर्माण उपसंभाग अंबिकापुर. | सेतु पहुंच मार्ग. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

रा. प्र. क्र. 7/अ-82/2002-2003. —चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अर्थवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|------------------------|----------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | सूरजपुर | संजयनगर रविन्द्रनगर | 18.45 0.01 योग 18.46 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन ं संभाग; सूरजपुर. जिला सरगुजा. | महाबीरपुर जलाशय के डूबान एवं वेस्ट वियर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशनुसार, विवेक कुमार देवागंन,कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप–सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 मार्च 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
 - (क) जिला-रायगढ़
 - (ख) तहसील-खरसिया
 - (ग) नगर/ग्राम-छोटेडूमरपाली, प. ह. नं. 13
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.507 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में |
|------------|-----------------------|
| (1) | (2) |
| . 378 | 0.210 |
| 381 | 0.297 |
| योग | 0.507 |

- (2) सार्वजिनक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राबर्टसन रेल्वे स्टेशन के निकट साईडिंग निर्माण हेतु भू-अर्जन.
- (3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 मार्च 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
 - (क) जिला-रायगढ़
 - (ख) तहसील-खरसिया
 - (ग) नगर/ग्राम-कुनकुनी, प. ह. नं. 13
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.440 हेक्टेयर

| र | बसरा नम्बर | रकबा ' (हेक्टेयर में |
|-----|------------|-------------------------|
| | (1) | . (2) |
| | 245 | 0.071 |
| | 246/5, 8 | 0.060 |
| • | 247/10 | 0.052 |
| | 247/3 | 0.081 |
| | 247/4 | 0.028 |
| | 247/5 | 0.020 |
| | 248 | 0.040 |
| | 249/1 | 0.076 |
| | 250/1 | 0.012 |
| योग | 9 . | 0.440 |
| | | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रेल्वे साईडिंग निर्माण हेतु भू-अर्जन.
- (3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक ७ मार्च 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

| अनुस | रू ची | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|--|----------------------------------|------------|------------------------|
| | | (1) | (2) |
| | | (1) | ν=/ |
| (1) भूमि का वर्णन- | | 138 | . 0.008 |
| (क) जिला-रायगढ़ | | 141 | 0.713 |
| (ख) तहसील-खरसिया | | 143/3 | 0.194 |
| (ग) नग√ग्राम-सरवानी | | 148 | 0.032 |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल-1 | 1.428 हेक्टेयर | 149/1 | 0.146 |
| • | . • | 149/2 | 0.117 |
| खसरा नम्बर | रकबा | 149/3 | 0.129 |
| | (हेक्टेयर में) | 150/2 | 0.089 |
| (1) | (2) | 150/3 | 0.089 |
| | | 151/1 | 0.162 |
| 11/2 | 0.741 | 151/2 | 0.040 |
| . 12 | 0.162 | 151/3 | 0.012 |
| 13 | 0.069 | 151/5 | 0.125 |
| 14 | 0.105 | 154/1 | 0.210 |
| 106/3 | 0.125 | ا 154/2 | 0.259 |
| 107 | 0.186 | 154/3 | |
| . 106/1 | 0.040 | 155 | 0.004 |
| | | 156 | 0.077 |
| योग | 1.428 | 157/1 | 0.028 |
| · | <u> </u> | 158 | 0.255 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके वि | | 161/1 | 0.121 |
| से खरसिया शाखा नहर के वि | वतरण एवं लघु नहर हतु. | 161/2 | 0.020 |
| (-) — — — — — — — — — — — — — — — — — | /\ | 170/2 | 0.243 |
| (3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा(राजस्व) खरसिया के कार्यात | | 171/1 | 0.028 |
| (राजस्व) खरासया क काया | त्रय म देखा जा सकता है. | 171/2 | 0.105 |
| रायगढ, दिनांव | न मार्च २००३ | . 171/3 | 0.186 |
| राष्ट्राष्ट्र, दिनाप | 7 414 2003 | ` 172 | 0.024 |
| भ-अर्जन एकरण कमांक 1 | 6/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य | 194/1 | 0.057 |
| शासन को इस बात का समाधान हो | गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के | 194/2 | 0.105 |
| | के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक | 194/3 | 0.243 |
| प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. | अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 | 195/1 | 0.004 |
| (क्रमांक एक सन् 1984) की ध | ारा ६ के अन्तर्गत इसके द्वारा | 195/8 | 0.194 |
| | ठक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के | 195/10 | 0.170 |
| लिए आवश्यकता है :— | | 202/1 | 0.081 |
| | • | 202/3 | 0.053 |
| अनु | सूची | 204/1 | 0.174 |
| | | 215/1 | 0.178 |
| (1) भूमि का वर्णन- | | 215/2 | 0.036 |
| (क) जिला-रायगढ़ | | 216/2 | 0.053 |
| (ख) तहसील-खरसिय | मा · | 216/4 | 0.004 |
| (ग) नगर⁄ग्राम-लोधिय | ग | | |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल- | -5.785 हेक्टेयर | | |

| | | • | | |
|-----------|----------------------------------|---|---------------|----------------|
| | (1) | (2) | (1) · | (2) |
| • | 232/1 | 0.049 | 187/4 | · 0.279 |
| | 235 | 0.458 | 188/2 | 0.020 |
| | 161/3 | 0.287 | 189 | 0.020 |
| | 232/2 | 0.049 | 190 | |
| | 232/3 | 0.101 | 192/1 | 0.028 0.105 |
| | 157/2 | 0.045 | 197 | 0.103 |
| | 157/3 | 0.028 | 198 | 0.012 |
| | | | 223 | 0.037 |
| योग | 46 | 5.785 | 225 | 0.117 |
| | | | 229 | 0.004 |
| (2) सार्व | जनिक प्रयोजन जिस | प्रके लिए आवश्यकता है—टर्न की पद्धति | 230 | 0.202 |
| | | के वितरण एवं लघु नहरं हेतु. | 231/1 | 0.202 |
| | | . | 237 | 0.045 |
| (3) उक्त | भू-खण्ड का नः | क्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी | 233/1 | 0.043 |
| | •• | कार्यालय में देखा जा सकता है. | 233/1 | 0.409 |
| | | | 297/2 | 0.409 0.186 |
| | | | 298 | 0.081 |
| | रायगढ़, वि | देनांक 7 मार्च 2003 | 300 | 0.061 |
| | | • | 301/1 | 0.057 |
| | | क 17/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य | - 305 | 0.037 |
| | | न हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के | 308 | 0.053 |
| | | नुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक | 309 | 0.033 |
| | | है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 | 310 | |
| | | ी धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के | 311 | 0.053 0.093 |
| | त ।कया जाता ह ।श्यकता है :— | ाक उक्त भूमि का उक्त प्रयोजन के | 313 | 0.093 |
| 1(1) 9(1) | . 9 11.0 | • | 314/6 | 0.125 |
| | | थनग्रनी | · 451/2 | 0.150 |
| | ` | अनुसूची | 453 | 0.036 |
| (1) 01 | मि का वर्णन- | • | 454 | 0.012 |
| | -` | · | 455 | 0.093 |
| | (क) जिला-रायग (ख) तहसील-खर | • | 457/1 | 0.077 |
| | (ख) तहसाल-खर (ग) नगर/ग्राम-ढि | | 457/2 | 0.162 |
| | • | नाना हल−5.230 हेक्टेयर | 458 | 0.125 |
| | (भ) लगमग क्षत्रप | ००-5.230 हक्टपर | 459 | 0.049 |
| 38 | ासरा नम्बर | रकबा | 460/1 | 0.243 |
| G | तिरा गन्थर | रकथा (हेक्टेयर में) | 461 | 0.235 |
| | (1) | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 476/1 | 0.093 |
| | (1) | (2) | 476/2 | 0.101 |
| | 118 | . 0.125 | 476/3 | 0.121 |
| | | 0.125 | 477 | 0.040 |
| | 119 | 0.008 | . 478 | 0.267 . |
| | 181 | 0.441 | 17.5 | 0.207 |
| | 187/1 | 0.024 | | |
| | 187/2 | 0.344 | | |

| | (1) | • | (2) |
|-----|-----|---|-------|
| • | 483 | | 0.040 |
| योग | 47 | | 5.230 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.
- (3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर्, दिनांक 13 जनवरी 2003

क्रमांक भू-अर्जन/10/अ/82 वर्ष 2001-2002. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उस्नेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
 - (क) जिला-रायपुर
 - (ख) तहसील-कसडोल
 - (ग) नगर/ग्राम-चांदन
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.08 एकड़

| खंसरा नम्बर | रकबा |
|-------------|------------|
| | (एकड़ में) |
| (1) | ` (2) |
| 34/3/ख | 0.11 |

| योग 4 | 1.08 |
|--------|-------|
| 34/2 ख | 0.02 |
| 43/6 क | |
| 43/5 क | |
| 40/2 | |
| 35/1 | |
| 34/3 क | 0.78 |
| 34/3 ভ | 0.17 |
| (1) | . (2) |
| | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अमरूवा जलाशय के अंतर्गत चांदन वितरक नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुरे, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1 अ/अ/82 वर्ष 2002-2003.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
 - (क) जिला-रायपुर
 - (ख) तहसील-बिलाईगढ़
 - (ग) नगर⁄ग्राम-छपोरा
 - (घ) लंगभग क्षेत्रफल-0.352 हेक्टेयर

| 🗸 खसरा नम्बर | रकबा |
|--------------|----------------|
| | (हेक्टेयर में) |
| (1) | (2) |
| 586/2 | 0.089 |
| 587 | 0.156 |
| 588 | 0.008 |

| | (1) | (2) |
|-----|-------|-------|
| | 586/1 | 0.097 |
| योग | 4 | 0.352 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जोंक व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर्, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/2 अ/अ/82 वर्ष 2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

.अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
 - (क) जिला-रायपुर
 - (ख) तहसील-भटगांव
 - (ग) नगर/ग्राम-बेलटिकरी
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.432 हेक्टेयर

| र स | वसरा नम्बर | रकबा ं (हेक्टेयर में) |
|--------|------------|--------------------------|
| | (1) | (हक्टय(म) (2) |
| | 868 | 0.032 |
| | 178 | 0.078 |
| | 179 | 0.322 |
| योग | 3 | 0.432 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जोंक व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/3 अ/अ/82 वर्ष 2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
 - (क) जिला-रायपुर
 - (ख) तहसील-भटगांव
 - (ग) नगर/ग्राम-धारासीव⁻
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

| 7 | खसरा नम्बर | रकबा |
|-----|------------|----------------|
| | | (हेक्टेयर में) |
| | (1) | (2) |
| | 205 | 0.085 |
| योग | 1 | 0.085 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जोंक व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण,
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर दिनांक 17 फरवरी 2003

त्रमांक-क/भू-अर्जन/4 अ/अ/82 वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
 - (क) जिला-रायपुर
 - (ख) तहसील-बिलाईगढ़
 - (ग) नगर/ग्राम-बिलाईगढ़
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.016 हेक्टेयर

| • | षसरा नम्बर | रकबा |
|-----|------------|----------------|
| | | (हेक्टेयर में) |
| | (1) | (2) |
| | 818/1 | 0.016 |
| योग | 1 | 0.016 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जोंक व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

